



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 798 राँची, सोमवार

27 कार्तिक, 1937 (श०)

19 अक्टूबर, 2015 (ई०)

---

ग्रामीण विकास विभाग  
(पंचायती राज)

-----

संकल्प

16 अक्टूबर, 2015

संख्या-3053--पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने की लिए 11वीं अनुसूची एवं झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा- 75] 76 एवं 77 में वर्णित विषयों से संबंधित शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए विभागों के द्वारा संकल्प निर्गत किये गए। इन संस्थाओं यथा- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को एक स्वशासी निकाय के रूप में शक्तियों के क्रियान्वयन

हेतु तीन विभागों- स्कूल, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के संकल्पों के संदर्भ में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

(क) स्कूल, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग :-

- (i) ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी समिति(मुखिया एवं वार्ड सदस्यों) ही प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यों का त्रैमासिक समीक्षा करेगी एवं समीक्षा प्रतिवेदन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधीक्षक को समर्पित करेगी ।
- (ii) ग्राम पंचायत हर माह कम से कम एक बार प्रत्येक विद्यालय में दिये जाने वाले मध्याह्न भोजन का निरीक्षण सुनिश्चित कराएगा । इसके लिए प्रत्येक वार्ड में एक समिति गठित होगी जिसमें उस वार्ड के सदस्य के साथ विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक अवश्य शामिल रहेंगे जो वार्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यालय का निरीक्षण निरीक्षण करेंगे । संबंधित प्रतिवेदन मुखिया के माध्यम से ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी समिति को समर्पित किया जाएगा ।
- (iii) पंचायत के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश मुखिया के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा । हर ग्राम पंचायत को आकस्मिक अवकाश हेतु पंजी संधारित करना अनिवार्य होगा ।
- (iv) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का वेतन का भुगतान मुखिया की उपस्थिति विवरणी/अनुशंसा के आधार पर होगा । प्रशासी विभाग द्वारा इस हेतु विहित प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा ।

(ख) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग :-

- (i) समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रखण्ड स्तर पर प्रमुख एवं सदर अस्पताल के प्रबंध समिति के अध्यक्ष जिला परिषद् अध्यक्ष होंगे ।
- (ii) ग्राम पंचायत के माध्यम से यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि स्वास्थ्य केंद्रों/ उप केंद्रों पर चिकित्सक पूर्व से निर्धारित तिथियों पर अवश्य जाएँ । चिकित्सकों द्वारा केन्द्रों पर जाने से संबंधित मासिक प्रतिवेदन मुखिया के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/असैनिक शल्य चिकित्सक को प्रेषित की जाएगी । इसी आधार पर उनके वेतन भुगतान की कारवाई होगी।
- (iii) ए०एन०एम० को अवकाश की स्वीकृति संबंधित पंचायत के मुखिया से लेनी होगी तथा मुखिया के मासिक उपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर ही ए०एन०एम० के वेतन का भुगतान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

- (iv) प्रखण्ड स्तर पर पदस्थापित प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्रमुख के द्वारा दी जाएगी । इससे संबंधित पंजी का संधारण पंचायत समिति समिति के कार्यपालक पदाधिकारी/सचिव द्वारा की जाएगी ।
- (v) जिला स्तर पर असैनिक शल्य चिकित्सक के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा दी जाएगी । इससे संबंधित पंजी का संधारण मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् के द्वारा किया जाएगा।
- (ग) ग्रामीण विकास विभाग :-
- (i) मनरेगा अंतर्गत सेल्फ ऑफ़ प्रोजेक्ट में शामिल एवं उसमें निहित प्राथमिकताओं के आधार पर एवं तकनीकी तथा अन्य रूप से सन्तुष्ट होने पर 10.00 लाख रुपये तक की योजनाओं की स्वीकृति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी । ऐसे स्वीकृत योजनाओं को पंचायत समिति के आगामी बैठक में अनुमोदित कराना आवश्यक होगा ।
- 2 पूर्व के आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।
- 3 दिनांक 14.10.2015 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या 3 के रूप में स्वीकृत।

संचिका संख्या – 1 स्था०(वि०) – 145/2015

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),

सचिव

ग्रामीण विकास विभाग

(पंचायती राज)

-----